[श्री सत्यनारायण जटिया]

बनाने की आवश्यकता है। कर्मचारियों की कमी की समुचित मात्रा में नियुक्ति कर दूरभाष केन्द्रों की कार्य क्षमता बढ़ाने से उपभोक्ताओं को यथोचित सेवा प्राप्त कराना चाहिए।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि दूरभाष सेवा को अधिक कार्यक्षम बनाने हेतु पर्याप्त उपाय किये जाएं तथा उज्जैन, रतलाम, नीमच के दूरभाष केन्द्रों का विस्तार कर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

(vii) Need to shift the present telegraph office at Burdwan and to open some more Telegraph offices there

SHRI SUSHIL BHATTACHARYYA (Burdwan) : I would like to invite immediate attention of the Government to the insufferable inconvenience caused to the public in the absence of an adequate number of telegraph offices in the city of Burdwan. The only tetegraph office which is supposed to serve more than three lakhs of people is at present accommodated in the first floor of a rented house in a blind alley. The rent is out of all proportion to the accommodation provided for and that too, in an ill-ventilated building, the roof of which collapsed recently. Burdwan, besides being the district headquarters, is a growing city of importance having a university campus within the city and with far-flung area requires pretty badly a telegraph office in each zonal postal area. The present telegraph office, too, needs, to be moved to the telephone exchange building for greater convenience of customers.

(viii) Need to lay down norms aud guidelines for the distribution of loans by banks under mass loaning scheme

DR. A. KALANIDHI (Madras Central) : Under the 20-Point Programme, nationalised banks are being asked to arrange to find out eligible unemployed youths for disbursement of loans. Though there are no norms nor guarantors for such loans, yet the Managers of the branches of the Banks are held responsible for their failure to recover the loans disbursed. The managers are not given enough time to scrutinise the applications received by them and they are compelled to disburse the loans within a short time. By this kind of loan disbursement, the interets of the depositors are not safeguarded and people will lose their faith in the banking system. It is understood that a sum of Rs. 46.00 crores is to be disbursed in each State. Thus a colossal amonut will be involved in this kind of disbursement of loans, without taking any security for the same. I, therefore, request that certain guidelines and rules be framed for disbursement of loans by the Government and the interests of the depositors as well as the Government be safeguarded. The banks should be given a free hand to choose the prospective loanees to ensure the repaying of the disbursed loans and utilisation of the loan amount towards productivity and employment to the unemployed youths.

(ix) Need to provide drinking water in Barmer, Jaisalmer and Jodhpur districts

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त के थार रेगिस्तानी क्षेत्रों विशेषत: बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में पीने के पानी की समस्या राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपये व्यय करने के उपरान्त भी अभी तक आधे से अधिक ग्रामों में गंभीर से गंभीरतम बनी हुई है।

उक्त जिलों में तिहाई हिस्से में नजदीक में पानी का कोई स्रोत नहीं है जो नलकूप बनाये गये हैं उनमें से अधिकांश में बहुत

कम पानी आया या बिल्कुल नहीं आया या बहुत ही खारा पानी आया ।

नलकूपों और कुओं के निर्माण से उक्त जिलों में स्थायी तौर से पीने के पानी की समस्या का हल नहीं किया जा सकता ।

इतने विशाल क्षेत्र में मनुष्यों एवं पशुओं को पानी पिलाने का स्थायी हल राजस्थान केनाल द्वारा ही किया जा सकता है ।

अत: केन्द्र एवं राज्य सरकार से पुरजोर निवेदन है कि राजस्थान प्रान्त के बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों के सैकड़ों ग्रामों में पानी पहुंचाने के लिये राजस्थान नहर के पोकरण लिफ्ट केनाल एवं लीलवा ब्रांच के गहरा रोड तक की स्वीकृति देकर इन नहरों से पीने के पानी की योजनाएं बनाकर सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस थार में रेगिस्तान क्षेत्र में पीने के पानी का स्थायी हल करें ।

———

12.44 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF THE INCHEK TYRES LIMITED AND NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LIMITED (NATIONALISTION) ORDINANCE

AND

INCHEK TYRES LIMITED AND NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LIMITED (NATONALISATION) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up further discussion on the Statutory Resolution moved by Prof. Saif-Ud-Din Soz on 3rd March, 1984 and further consideration of Inchek Tyres Limited and National Rubber Manufacturers Limited (Nationalisation) Bill moved by Shri Pattabhi Rama Rao on 3rd March, 1984.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1984 जो प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। ये दोनों कंपनियां काफी अर्से से नुकसान में चल रही थीं। यह जो राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया गया है, यह यद्यपि विलंब से उठाया गया है तो भी सही कदम उठाया गया है। इसलिए मैं इस कदम का स्वागत करता हूं।

हम यह देख रहे हैं कि प्राय: उद्योग सिक होते जा रहे हैं। इसीलिए हर अधिवेशन में अक्सर इस प्रकार के विधेयक प्रस्तुत होते हैं और हमें उद्योगों के राष्ट्रीकरण की ओर कदम बढ़ाना पड़ता है। यह कहा जाता है कि हमारे जो प्राईवेट सेक्टर के उद्योग हैं, वे सक्सेसफुल्ली रन नहीं कर रहे हैं। वे प्राफिट में नहीं चल रहे हैं, बड़े-बड़े उद्योग प्राईवेट स्तर पर सक्सेफुल चल रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि उनको सिक इंडस्ट्रीज घोषित किया जा रहा है। इस प्रकार की स्थति है कि उन उद्योगों को बन्द कर दिया जाता है और मजदूरों के सामने अनएम्प्लायमेंट की समस्या खड़ी हो जाती है राज्य सरकारों के सामने और केन्द्र सरकार के सामने यह समस्या बनी रहती है। पहले भी बंबई की टेक्सटाइल मिल्स के बारे में हमें इस तरह का निर्णय लेना पड़ा और वे एक साल तक बंद रहीं। इस प्रकार इस विषय में जो एम्प्लायर्स का जो स्टैंड है उसके बारे में हमें पूरी तरह से